भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 858

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन

858. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल राज्य में सड़कें खराब निर्माण मानकों, भारी वर्षा और अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियों के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में बार-बार सड़क क्षति और सड़क सतहों के खराब स्थायित्व के मूल कारणों की पहचान करने के लिए पिछले पाँच वर्षों में कोई वैज्ञानिक अध्ययन या तकनीकी मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अध्ययन किए गए हैं, इसमें कौन-कौन सी एजेंसियाँ शामिल हैं और ऐसे अध्ययन/मूल्यांकन के तहत प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार केरल में वैज्ञानिक सड़क डिज़ाइन, बेहतर निर्माण गुणवत्ता, बेहतर जल निकासी और सुदृढ़ रखरखाव प्रथाओं को अपनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है ताकि बार-बार होने वाली क्षति को रोका जा सके और भविष्य में सड़कों का जीवनकाल बढ़ाया जा सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-66 पर निर्माणाधीन कुछ खंडों को नुकसान पहुँचा है। इन्हें संबंधित रियायतग्राहियों/ठेकेदारों द्वारा अपने खर्च पर ठीक किया जाना है, क्योंकि वे अनुबंध के तहत हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) परियोजनाओं में 15 वर्षों तक और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं में निर्माण पूरा होने के बाद 5 वर्षों (लचीले फुटपाथ)/10 वर्षों (कठोर फुटपाथ और संरचनाएँ) तक सड़कों का रखरखाव करने के लिए बाध्य हैं।

(ख) जी**,** नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए, सरकार गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों का पालन करती है। इन मानकों में वैज्ञानिक सड़क डिज़ाइन, बेहतर निर्माण पद्धतियाँ और सड़कों का जीवन काल बढ़ाने के लिए उचित जल निकासी उपायों के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर चल रही सभी परियोजनाओं में क्षति की संभावना वाले संवेदनशील स्थानों का आकलन करने और उचित उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

*****